मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा की सटीक रणनीति से खनन विभाग को मिला राष्ट्रीय सम्मान

किच्छा। उत्तराखंड के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय (DGM) ने खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी डिजिटल पहलों, MDTSS और ई-रवाना (e-Ravanna), के माध्यम से देश में एक मिसाल कायम की है। हाल ही में संपन्न स्कॉच समिट (SKOCH Summit) में विभाग की इन अत्याधुनिक प्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है।

MDTSS और ई-रवाना को पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई इन प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य खनन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना और जीरो लीकेज (Zero Leakage) सुनिश्चित करना है।

MDTSS (माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम): यह एक एकीकृत समाधान है जो खनन गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी करता है। इसमें वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) और ई-चेक गेट शामिल हैं, जो अवैध खनन पर लगाम लगाने में मदद करते हैं।

ई-रवाना (e-Ravanna) यह एक डिजिटल ट्रांजिट पास प्रणाली है। विभाग ने इसमें सुरक्षा सुविधाओं से लैस Security Paper को शामिल किया है, जिससे फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग को रोका जा सके। उत्तराखंड खनन विभाग की इस कार्य प्रणाली को स्कॉच समिट में सम्मान और राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल हुई है।

स्कॉच ग्रुप द्वारा इन नवाचारों को शासन और विकास में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड खनन विभाग के निदेशक राजपाल लेघा (Rajpal Legha) के नेतृत्व में विभाग ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। इन सुधारों के चलते उत्तराखंड का खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1,200 करोड़ से अधिक हो गया है। खनन क्षेत्र में सुधारों और पारदर्शी कामकाज के लिए भारत सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लेघा की पारदर्शी और पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप नीतियों को सटीक रूप से धरातल पर लागू करने से उत्तराखंड की खनन नीति को स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (SMRI) में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन तकनीकी सुधारों के सफल क्रियान्वयन के बाद विभाग अब खनन क्षेत्रों में अत्याधुनिक कमांड सेंटर और सैटेलाइट-आधारित निगरानी को और मजबूत कर रहा है। उत्तराखंड के खनन विभाग को SKOCH Summit में मिले सम्मान और इसकी डिजिटल प्रणालियों—MDTSS एवं ई-रवाना (e-Ravanna)—पर विस्तृत तकनीकी और आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड खनन विभाग की इस पारदर्शी कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान मिला है।यह एक एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान है जिसे अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके मुख्य तकनीकी घटक निम्नलिखित हैं:

इंटेलिजेंट चेक गेट्स: राज्य के 4 चार प्रमुख जिलों (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, और उधम सिंह नगर) में 40 से अधिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं।

एडवांस्ड हार्डवेयर: इन गेट्स पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे, बुलेट कैमरे, RFID रडार और LED फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, जो वाहनों की 24/7 निगरानी करती हैं।

कमांड सेंटर: देहरादून में एक केंद्रीय माइनिंग स्टेट कंट्रोल सेंटर (MSCC) बनाया गया है, जो जिलों के मिनी कमांड सेंटरों से जुड़ा है।

रियल-टाइम ट्रैकिंग: वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) के माध्यम से खनिजों के परिवहन की लाइव निगरानी की जाती है ताकि ट्रांजिट पास में दिए गए गंतव्य से विचलन न हो। ई-रवाना (e-Ravanna) प्रणाली यह पोर्टल खनन लीज की निगरानी और डिजिटल ट्रांजिट पास जारी करने के लिए उपयोग किया जाता है।

सुरक्षा फीचर्स: फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग ने Security Paper युक्त ई-ट्रांजिट पास पेश किए हैं, जिनकी ट्रेनिंग जुलाई 2025 में अधिकारियों को दी गई थी

पारदर्शिता: इस पोर्टल के माध्यम से सभी भुगतान और सेवाएं ऑनलाइन की जाती हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है।

आर्थिक प्रभाव और उपलब्धियां इन तकनीकी सुधारों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं:

राजस्व में भारी वृद्धि: राज्य का खनन राजस्व जो पहले 300 करोड़ था, वह बढ़कर 1,200 करोड़ तक पहुँच गया है। अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व 1,100 करोड़ के पार रहा।

राष्ट्रीय रैंकिंग: उत्तराखंड ने भारत सरकार के स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स (SMRI) में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रोत्साहन राशि: बेहतर सुधारों के लिए केंद्र सरकार की SASCI योजना के तहत उत्तराखंड को 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई है।

स्कॉच (SKOCH) सम्मान का महत्व

SKOCH अवार्ड को शासन और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान माना जाता है। उत्तराखंड के खनन विभाग को यह पुरस्कार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में उनके पारदर्शी और राजस्व-बढ़ाने वाले मॉडल के लिए दिया गया है, जिसे अब अन्य राज्य भी अपनाने पर विचार कर रहे हैं। इस सम्मान से एक बात तो स्पष्ट होती है कि विपक्ष तथा सत्ताधारी पार्टी के ही लोग चाहे जितने आरोप लगाए लेकिन उत्तराखंड की खनन नीति अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का काम कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान से निश्चित रूप से उत्तराखंड के खनन विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए संजीवनी का काम करेगी और आलोचना करने वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। निश्चित रूप से यह उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के कुशल नेतृत्व और खनन निदेशक राजपाल लिखा कि बेहतर कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है।